



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 947]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 19, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक FINACC-3901/420/2025.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के शासकीय क्रय से संबंधित विधि की प्रासंगिकता एवं स्पष्टता के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्-

- नियम-2 (एवं इसके उपनियम) के स्थान पर, निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"नियम-2 (1) ये नियम समस्त विभाग तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एवं/या उनसे बजट प्राप्त करने वाले कार्यालयों पर लागू होंगे।

(2) उपरोक्त उपनियम के होते हुए भी, परिशिष्ट-1 में वर्णित संस्थाओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

(3) इन नियमों में “स्टार्ट-अप” से आशय ऐसे स्टार्ट-अप से है जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है एवं जो निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाइट पर वैध पाया गया है।

(4) इन नियमों में “सूक्ष्म एवं लघु उद्योग” से छत्तीसगढ़ में स्थापित एवं औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की परिभाषा अनुसार मान्य, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं, जो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं उत्पादन प्रमाण-पत्र/संचालन प्रमाण-पत्र रखते हैं।”
- उपनियम-3.1.1 में शब्द-समूह “उनकी नियमावली, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये क्रय” का लोप किया जाए।
- उपनियम-4.2 के स्थान पर, निम्नानुसार उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

“उपनियम-4.2 (1) निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा। कोई अतिरिक्त शर्त ऐसी नहीं जोड़ी जा सकेगी, जो इन नियमों के प्रावधानों के परे, प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है। अतिरिक्त शर्तों का अनुमोदन, विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा विभागाध्यक्ष के क्रेता होने की स्थिति में, शासन द्वारा किया जाएगा।

(2) स्टार्ट-अप को और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को पूर्व अनुभव और टर्न-ओवर से छूट की शर्त जोड़ी जा सकेगी। इस छूट को, क्रेता कार्यालय लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य, गंभीर सुरक्षा संचालन व उपकरण सम्बन्धी एवं अन्य कोई समुचित कारण दर्शाते हुए समाप्त कर सकेगा।

(3) नियम 13 के अंतर्गत, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा एल-1 पर सहमति देने पर, उन्हें प्राप्त होने वाले क्रय-आदेश के प्रतिशत का निर्धारण शर्तों में किया जाएगा।

(4) वस्तुओं के क्रय में, क्रेता विभाग मरम्मत/ प्रतिस्थापन की शर्त जोड़ सकेगा।“

4. उपनियम-4.3.1 में,

(1) खंड (अ) में शब्द “तथा” एवं रु. 50,000 (पचास हजार)” के स्थान पर, शब्द “अथवा” एवं

“एक लाख रुपये” क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) खंड (ब) में शब्द “रुपये 50,000 (पचास हजार)” के स्थान पर, शब्द “एक लाख रुपये” प्रतिस्थापित किया जाए।

5. उपनियम-4.3.2 में, शब्द “रु. 50,001 से 3,00,000 (रुपये पचास हजार एक से रुपये तीन लाख)” के स्थान पर, शब्द “रु. 1,00,001 से 3,00,000 (रुपये एक लाख एक से रुपये तीन लाख)” प्रतिस्थापित किया जाए।

6. उपनियम-4.4 में के स्थान पर, निम्नानुसार उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

“उपनियम-4.4 निविदा विज्ञप्ति-

(1) जेम वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित करने की स्थिति में पूर्ण जानकारी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) जेम से भिन्न स्थिति में, निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा परिशिष्ट-3 में निर्धारित प्ररूप में प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि व समय तक निविदा स्वीकार की जाएगी, का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। क्रय की अन्य शर्तें एवं शर्तों के विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

(3) बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।“

7. उपनियम-4.5 की सारणी के स्थान पर, निम्नानुसार सारणी प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

“निविदा पद्धति	अवधि/दिवस		
	प्रथम आमंत्रण	द्वितीय आमंत्रण	तृतीय आमंत्रण
सीमित निविदा	10	7	5
खुली निविदा (रु. 10 लाख तक)	15	10	5
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक)	21	14	7
ग्लोबल निविदा	30	20	10”

8. उपनियम-4.7 के खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

“(ब) स्टार्ट-अप को और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट दी जाए।“

9. उपनियम-4.7.1 में निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्-

“परन्तु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या महिला वर्ग के स्वामित्व वाले, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को इस राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।“

10. उपनियम-4.9 में,

(1) खंड (ब) के स्थान पर निम्नानुसार खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

“(ब) क्रय हेतु चयनित निविदाकार को, क्रेता द्वारा इस हेतु सूचना देने के 15 दिवस के भीतर, राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, पंजीयन पश्चात ही क्रय आदेश जारी

किया जाए।“

(2) खंड (स) का लोप किया जाए।

11. उपनियम-4.10 में, वाक्य “उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जाए।” के स्थान पर, वाक्य “आवश्यक होने पर वस्तु/सेवा का नमूना प्राप्त किया जा सकेगा।” प्रतिस्थापित किया जाए।
12. उपनियम-4.11 में, शब्द-समूह “उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है तो,” का लोप किया जाए।
13. उपनियम-4.14 में,
 - (1) खंड (1) में शब्द-समूह “किसी भी स्थिति में” के स्थान पर, शब्द-समूह “वस्तुओं के क्रय की स्थिति में” प्रतिस्थापित किया जाए।
 - (2) खंड (1) में निम्नानुसार वाक्य जोड़ा जाए, अर्थात्-
“सेवा की स्थिति में, पूर्व निर्धारित दर पर ही, स्पष्ट लिखित कारणों से, 6 माह हेतु विस्तार दिया जा सकेगा; इस 6 माह पश्चात क्रय आदेश में पुनः विस्तार नहीं किया जा सकेगा।”
 - (3) खण्ड (3) में शब्द-समूह “पुनरावृत्ति आदेश” के पूर्व, शब्द-समूह “वस्तुओं के सम्बन्ध में,” जोड़ा जाए।
14. उपनियम-8.2 में,
 - (1) शब्द “छत्तीसगढ़” के पूर्व, शब्द-समूह “ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत,” जोड़ा जाए।
 - (2) शब्द-समूह “ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ” के स्थान पर, शब्द-समूह “छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड” प्रतिस्थापित किया जाए।
15. उपनियम-8.3 में,
 - (1) शब्द “सामग्री” के पश्चात, शब्द-समूह “जिनका निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर पंजीकृत हस्तशिल्पियों/बुनकरों द्वारा हुआ है,” जोड़ा जाए।
 - (2) शब्द-समूह “को ही प्रदान किया जाए” के स्थान पर, शब्द-समूह “को प्रदान करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा” प्रतिस्थापित किया जाए।
16. उपनियम-8.6 में शब्द-समूह “अथवा अनुबंधित पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप इकाईयों के माध्यम से” का लोप किया जाए।
17. नियम 8 में, उपनियम-8.6 के पश्चात, निम्नानुसार उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्-
“उपनियम-8.7 शासकीय योजनाओं के विज्ञापन सभी माध्यमों यथा- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, आदि से प्रचार-प्रसार का कार्य छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से कराया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।”
18. नियम-13 (एवं इसके उपनियम) के स्थान पर, निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-
“नियम 13 (1) स्टार्टअप को क्रेता, न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल-1) के बराबर करने की सहमति तथा गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में, कुल क्रय राशि का 1 प्रतिशत, अधिकतम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में, क्रय

आदेश हेतु प्राथमिकता दे सकेगा।

(2) यदि किसी क्रय प्रक्रिया में न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल-1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से भिन्न का है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा निवेदित राशि एल-1 से 15 प्रतिशत अधिक की राशि के भीतर है, तो ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जो एल-1 पर आपूर्ति हेतु सहमत हों तथा गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंड सुनिश्चित करें, से कुल मिलाकर कुल क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत तक का क्रय किया जा सकेगा।“

19. परिशिष्ट-1 के स्थान पर, निम्नानुसार परिशिष्ट जोड़ा जाए, अर्थात् –

“परिशिष्ट -1

(नियम 2 देखें)

संस्थाएँ

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.